VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
R. N. 02 JUL 2018 NO. 03
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1067)

Name of Candidate	Sunil Kumar Dhanwanta		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	**Registration Number**	109506
Center	KB	**Date**	02-07-2018

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

Signature of Examiner

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
2. There are TWENTY questions printed in ENGLISH.
3. All questions are compulsory.
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

M-1/4, Plot No-A-12/13, Ist Floor, Ansal Building, Dr. Vidya Sagar Homeopathic Clinic, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What is the role that opposition plays in a democracy like India? In this context, discuss whether our Parliament can benefit from a shadow cabinet. **(150 words) 10**

भारत में परम्परा के तहत ~~उस पार्टी~~ विपक्ष की पार्टियों का लोकतंत्र में काफी योगदान रहा है।

इनकी प्रमुख भूमिकाएं निम्न हैं -

(क) सरकारों को अपने निर्णयों व नीतियों के प्रति ~~[illegible]~~ जागरूक बनाना

(ख) संसद एव विधानमण्डल में ~~पर्याप्त~~ लोक महत्त्व के मुद्दों पर पर्याप्त बहस को जन्म देना

(ग) जनता को सरकार की कमियों के खिलाफ जागरूक करना

(घ) विधि निर्माण में पर्याप्त भागीदारी

(च) परन्तु विपक्ष कभी-कभी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता है

(छ) संसद या राज्यविधानमण्डल के सत्रों में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

गतिरोध पैदा करता है

(ज) जनता को कभी-कभी गुमराह करने का प्रयास भी करता है।

इसी संबन्ध में छाया मंत्रिमण्डल से निम्न लाभ मिल सकते हैं -

(i) नीति निर्माण में तीव्रता व प्रभावशालिता

(ii) कानून निर्माण में अनेक विचारधाराओं के समावेश से उसकी प्रभावशीलता व स्वीकार्यता में वृद्धि

(iii) समय व धन की बचत

छाया मंत्रिमण्डल की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है जिसमें विपक्ष के कुछ प्रभावशाली लोग मिलकर सरकार की नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अतः छाया मंत्रिमण्डल के संसद में अनेक लाभ हैं परन्तु इस संबन्ध में चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Where there is a right, there is a remedy. In this context, discuss the nature and significance of writs in India with adequate examples. **(150 words) 10**

भारत के संविधान के ~~अनुच्छेदों के~~ अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

भारत में रिटों की प्रकृति -

(i) अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है ये हैं- परमादेश, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार पृच्छा।

(ii) उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ-साथ विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं अतः यह शक्ति व्यापक है।

(iii) अनुच्छेद 32 भी एक प्रकार का मूल अधिकार है अतः सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता

रिटों का महत्व -

(i) ~~अ~~ नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा जिसके अन्तर्गत समय-समय पर न्यायपालिकाओं ने

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अनेक रिट जारी की है।

(ब) सरकार के अतिशय व्यवहार के द्वारा नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन पर रोक

(स) यह ~~व्यव~~ अधीनस्थ न्यायालयों व लोक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है तथा उन्हें जवाबदेह बनाने में सहायक है।

अतः कहा जा सकता है कि अधिकारों की रक्षा के लिए रिटों का अत्यन्त महत्त्व है। डॉ भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Enumerate the objectives of NITI Aayog. Also, discuss the performance of this body since its inception and suggest measures to make it more effective. **(150 words) 10**

नीति आयोग का गठन मंत्रीमण्डलीय प्रस्ताव के द्वारा 1 जनवरी, 2015 को किया गया जिसने पूर्ववर्ती योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया।

इसके निर्माण के पश्चात इसका प्रदर्शन :-

(क) 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति तथा 3 वर्षीय कार्ययोजना का निर्माण जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया

(ख) राज्यों की नीति व योजना निर्माण में सहभागिता बढ़ाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा

(ग) आकांक्षी जिलों के रूपांतरण कार्यक्रम का शुभारंभ

(घ) शिक्षा क, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक विकास के क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापने हेतु अनेक रिपोर्टों व सूचकांकों का विकास जैसे स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत

(च) राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का कार्य

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

(i) नदी जल विवाद व अन्य अन्तर्राज्यीय विवादों में प्रभावी भूमिका नहीं

(ii) संघ सरकार व विपक्षी राज्यों की सरकारों के मध्य प्रभावी सहयोग में कमी

सुझाव-

(i) सभी राज्यों व संघ सरकार के मध्य भरोसा/विश्वास के विकास का प्रयास करना

(ii) अन्तर्राज्यीय मुद्दों के निवारण का प्रयास करना

(iii) पर्याप्त शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देना

इस प्रकार उपर्युक्त प्रयासों के द्वारा इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि कर संघवाद को और मजबूत बनाया जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. In view of the political class's inability to develop and maintain conventions relating to the appropriate use of Article 356, the Supreme Court's decision in the Bommai case provided much needed clarity. Comment.

(150 words) 10

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रावधान है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

परन्तु इस अनुच्छेद के प्रावधानों की अस्पष्टता तथा राज्यपाल की स्वविवेक आधारित शक्तियों के कारण इसका अनेक बार दुरुपयोग किया गया है।

कर्नाटक राज्य के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई वाद में अपने निर्णय में इस अनुच्छेद के प्रावधानों को स्पष्ट करने का प्रयास किया था।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Press freedom and good governance are not mutually exclusive. They support each other while promoting a country's economic and human development. Comment. **(150 words) 10**

प्रेस की स्वतंत्रता ~~समाज~~ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) से व्युत्पन्न की गई है।

प्रेस की स्वतंत्रता के लाभ।

(i) इससे सरकार को जवाबदेह बनाने में सहायता मिलती है

(ii) जनता के विचारों का प्रभावी रूप से प्रकट होना।

(iii) सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी

(iv) सरकार को गलत निर्णय लेने से रोकना

(v) जनप्रतिनिधियों को स्वच्छ व ईमानदार बनाना

(vi) नीति निर्माण में जनता की भागीदारी में वृद्धि करना

परन्तु कई बार प्रेस की स्वतंत्रता के कारण नीति निर्माण में बाधा आती है जिससे इसके नकारात्मक पहलू ~~सामने~~ सामने आते है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

परन्तु इसके लिए प्रेस पर युक्तियुक्त निर्बंधनों का होना आवश्यक है।

प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है क्योंकि यह जनभागीदारी को बढ़ाकर व सरकार को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाकर सुशासन को स्थापित करने में सहायक होता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. SHGs have succeeded in delivering financial inclusion, but for them to evolve as viable business enterprise requires a different approach. Analyse in the context of the twin goals of rural growth and promotion of women's entrepreneurship. (150 words) 10

ऐसे संगठन जो अपने कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए लोगों को परस्पर एकत्रित होकर काम करने का अवसर देते है 'SHG' कहलाते है।

SHG का वित्तीय समावेशन में योगदान -

(i) समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध करवाना
(ii) बैंकिंग सेवाओं से छूटे लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देना

ग्रामीण विकास व महिला उद्यमिता के विकास हेतु SHG में भूमिका

(i) ग्रामीण लोगों ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना
(ii) कृषि विकास में योगदान देना
(iii) महिलाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण एवं कौशल समर्थन प्रदान करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) महिलाओं द्वारा बनाये गए उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था करना

(v) बैंकों से ऋण लेने के दौरान गारंटी प्रदान कर्ता की भूमिका निभाना

(vi) कृषि उत्पादों के विक्रय व विपणन में प्रभावी भूमिका निभाना

आवश्यक दृष्टिकोण-

(i) संगठन को वैज्ञानिक संरचना

(ii) समाज के सभी वर्गों की भागीदारी

(iii) लाभ से प्रेरित ना होकर सामाजिक हित का ध्यान रखना

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The focus of higher education in India has been on a select few Central or autonomous institutions where as the ones in states remain neglected. Commenting on the statement, highlight the significance of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in this context. **(150 words) 10**

RUSA को उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए 2013 में प्रारंभ किया गया था

RUSA का महत्व.

(i) राज्य विश्वविद्यालयों की आधारभूत संरचना का विकास करना

(ii) राज्य विश्वविद्यालयों को स्वयत्तता प्रदान कर उनकी वित्तीय सहायता करना

(iii) प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना

(iv) कौशल विकास पर बल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Discuss the role played by PRIs in political empowerment of women. Also, suggest measures to further increase their political participation.

(150 words) 10

पंचायतीराज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थापित किया गया.

भूमिका.

(i) महिलाओं को अनिवार्य 33% आरक्षण के द्वारा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना

(ii) महिलाओं में नेतृत्वक्षमता का विकास करना

(iii) महिलाओं को सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए प्रेरित करना

(iv) महिलाओं के मनोबल को बढ़ाना

सुझाव.

(i) 'सरपंचपतियों' की संकल्पना को समाप्त कर महिलाओं को असली अर्थों में नेतृत्वकर्ता बनाना

(ii) आरक्षण की सीमा को 50%. तक बढ़ाना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) महिलाओं को शिक्षित बनाकर जागरूकता में वृद्धि करना

(iv) नागरिक समाज का सहयोग लेना

9. What is Strategic Autonomy? Critically examine the elements of such a policy in India's contemporary foreign policy in the context of recent developments. **(150 words) 10**

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. IBSA and BRICS are both examples of India's quest for multialignment, however there are key differences in their orientation. Discuss in the context of the relevance of these groupings for India. **(150 words) 10**

IBSA - भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका

BRICS - ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका

BRICS की भूमिका -

यह उभरते हुए विकासशील देशों का संगठन है तथा विश्व की लगभग 40 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है।

(i) जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाने में भूमिका

(ii) WTO में भूमिका

(iii) आतंकवाद में भूमिका

(iv) आर्थिक, तकनीकी व सामाजिक क्षेत्र में सहयोग

IBSA -

(i) जलवायु परिवर्तन, ~~में भूमिका~~ के खिलाफ भूमिका

(ii) चीन के प्रभाव को कम करने में भूमिका

(iii) आर्थिक व तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

BRICS में चीन शामिल है जबकि IBSA में नहीं अतः भारत इसका प्रयोग चीन के ~~प्रयोग~~ प्रभाव को कम करने में कर सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. What are the various modes of Alternate Dispute Redressal (ADR) mechanisms available in India? Identifying the problems being faced by them, provide suggestions needed to increase their effectiveness.

(250 words) 15

न्यायपालिका के अलावा विवादों के निपटारे हेतु बने संस्थानों को वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की संज्ञा दी जाती है। भारत में इस संबन्ध में अनेक तंत्र उपलब्ध है-

(i) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण- यह केन्द्रीय लोक सेवाओं व अखिल भारतीय सेवाओं सहित अनेक सेवाओं के कर्मचारियों के विवादों का निपटारा करता है।

2) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण- पर्यावरण संबन्धी मुद्दों के लिए

3) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT)

(4) लोक अदालत

(5) परिवार न्यायालय

(6) DRT- 'Debt. Recovery Tribunal'

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इन संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ-

(क) इनके निर्णय अंतिम नहीं होते तथा इनके निर्णयों के खिलाफ न्यायालयों मे अपील हो सकती है जिससे इनकी उपयोगिता कम हो जाती है

(ख) इनके पास पर्याप्त कर्मचारी बल का अभाव है

(ग) इनके पास केसों की संख्या बहुत ज्यादा है

(घ) बजटीय सहायता भी पर्याप्त नहीं तथा दण्ड देने की पर्याप्त शक्ति नहीं

सुझाव-

(क) विशेष परिस्थितियों में ही अपील करने की सुविधा

(ख) इनको पर्याप्त प्रशासनिक व बजटीय सहायता उपलब्ध करवाना चाहिए

(ग) अलग- अलग क्षेत्रों के लिए अलग - अलग तंत्रों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की स्थापना ताकि केसों का बोझ कम हो

(9) न्यायपालिका के हस्तक्षेप में कमी

इस प्रकार उपर्युक्त सुझावों द्वारा इन तंत्रों को प्रभावी शाली बनाकर न्यायपालिका के केसों के बोझ को कम कर लोगों को त्वरित न्याय दिया जा सकेगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. While the power to punish for the contempt of court is a much needed tool to protect the administration of justice from being maligned, it is time that it be relooked into. Critically analyse. **(250 words) 15**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति दी गई है तथा यह शक्ति अन्य प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है।

न्यायालय की अवमानना के खिलाफ दण्ड देने की शक्ति को न्यायालय की निष्पक्षता व प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ इसके निम्नलिखित सकारात्मक पहलू भी है -

(क) न्यायपालिका के निर्णयों के खिलाफ अवांछित टिप्पणियों पर रोक

(ख) न्यायधीशों की ~~प्रतिष्ठा~~ व प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता की रक्षा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ग) न्यायपालिका के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक

(घ) न्यायपालिका की स्वतंत्रता व शुचिता को बनाये रखने में इसकी भूमिका

(ङ) न्यायपालिका पर विश्वास को बनाये रखने में सहायक जो अत्यन्त आवश्यक है।

इसी के साथ इसके निम्नलिखित नकारात्मक पहलू भी है.

(क) अवमानना को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है तथा यह न्यायालय के विवेक पर आधारित है जिससे इसके दुरुपयोग की संभावना है।

(ख) दण्ड की मात्रा के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं

(ग) इससे न्यायपालिका में अपारदर्शिता में वृद्धि हो सकती है।

(घ) इससे न्यायपालिका के द्वारा ~~व्यक्ति~~ व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करने की संभावना है।

अतः इस शक्ति को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। अवमानना की शक्ति के प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या व उन्हें संहिताबद्ध किया जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन कायम हो सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Criminalisation of politics remains a key concern for the Indian political system. In this context, analyse the role played by the Supreme Court and Election Commission over the years. Also, in what ways can the media play a positive role? **(250 words) 15**

~~संविधान~~ राजनीतिक व्यवस्था में ~~अपराधिक~~ आपराधिक लोगों के प्रवेश को राजनीति के आपराधीकरण की संज्ञा दी जाती है। संविधान समीक्षा आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग तथा चुनाव आयोग ने समय-समय पर इस संबन्ध में अपनी चिन्ताएँ व्यक्त की है।

राजनीति के आपराधिकरण को रोकने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका -

(क) सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका है जो अपराधी साबित हो चुके है

(ख) सुप्रीम कोर्ट ने ~~अपराधियों~~ उन राजनेताओं के मामलों के निपटारे हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का सुझाव दिया है जिन पर अपराधिक मामले लंबित है

(ग) सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में सुधार की सिफारिश की है

(घ) आचार संहिता को और अधिक कठोर बनाने का सुझाव दिया।

(च) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 A की कठोर व्याख्या की है।

चुनाव आयोग की भूमिका

(क) आचार-संहिता को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है

(ख) कुख्यात अपराधी शहाबुद्दीन का नाम निर्वाचन ~~पत्र~~ मतावली (वोटर लिस्ट) से हटाकर कठोर संदेश दिया

(ग) अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने हेतु संसद को सुझाव दिए

परन्तु उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद भी संसद एवं विधानसभाओं में अनेक राजनेता विद्यमान हैं जिन पर अनेक गंभीर अपराधिक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मामले चल रहे है।

इस संबंध में मीडिया की भूमिका-

(क) अपराधी नेताओं के खिलाफ जनमत तैयार करने में सहयोग देना

(ख) जनता को जागरूक बनाना

(ग) अपराधी नेताओं के क्रियाकलापों का पर्दाफाश करना

राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर चुनौति बन चुका है जिसका शीघ्र उन्मूलन आवश्यक है क्योंकि अपराध करने वाला अपराध के खिलाफ कानून बनाने वाला नहीं हो सकता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Highlight, in brief, the mandate of the National Commission for Minorities (NCM). Identify the different challenges that the commission faces and suggest measures to address them. **(250 words) 15**

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया गया था जिसके तहत भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान की गई है।

इस आयोग को निम्नलिखित अधिदेश सौंपे गए हैं–

(क) अल्पसंख्यकों के लिए संविधान एवं अन्य कानूनों में उपस्थित प्रावधानों की समीक्षा करना

(ख) सरकार को अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में किसी समुदाय को जोड़ने या हटाने की सिफारिश करना

(ग) अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की जाँच कर उस पर महत्त्वपूर्ण सुझाव देना

(घ) राष्ट्रपति को इस संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन देना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपर्युक्त अधिदेशों के बावजूद इस आयोग को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है-

(क) आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति तो है परन्तु दण्ड देने की शक्ति नहीं।

(ख) आयोग के पास विशेषज्ञों की कमी है

(ग) आयोग की संरचना में वैज्ञानिक दोष है क्योंकि इसमें केवल अल्पसंख्यकों को ही शामिल किया जाता है जो तार्किक प्रतीत नहीं होता

(घ) आयोग में दूरदर्शिता एवं पारदर्शिता का अभाव है तथा इस संबन्ध में सरकार का रुख भी नकारात्मक प्रतीत होता है।

उपर्युक्त चुनौतियों के अलावा भी आयोग के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं जिनके समाधान के बिना इसको प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। अतः आयोग से संबन्धित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियों के समाधान के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए -

(क) आयोग को अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों के मामलों में दण्ड देने की शक्ति दी जानी चाहिए

(ख) आयोग को विशेषज्ञों तथा सरकार का पर्याप्त सहयोग प्राप्त होना चाहिए

(ग) सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए

(घ) आयोग की संरचना एवं कार्यशैली को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

उपर्युक्त समाधानों के साथ-साथ आयोग के साथ नागरिक समाज एवं जनभागीदारी को जोड़ना चाहिए तथा इसे दन्तहीन संस्था के स्थान पर प्रभावी संस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि अल्पसंख्यों का कल्याण सुनिश्चित हो सके ।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The recent decision of the government to open up positions at the senior levels in bureaucracy through lateral entry is an important but only small step in the direction of much needed reforms in the higher civil services. Analyse. **(250 words) 15**

हाल ही में सरकार द्वारा 'संयुक्त सचिव' स्तर के पदों पर पार्श्व प्रवेश के माध्यम से भर्ती के संबन्ध में विज्ञापन निकाला गया। वस्तुतः पार्श्व भर्ती सरकारी पदों पर बिना प्रवेश परीक्षा के निजी क्षेत्र के लोगों के प्रवेश से संबन्धित है।

समय-समय पर सिविल सेवा में सुधार की मांग उठती आयी है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग इत्यादि ने पार्श्व भर्ती के संबन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

पार्श्व भर्ती के द्वारा प्रशासन में निम्नलिखित लाभों की अपेक्षा की जा रही है-

(क) सरकारी सिविल सेवकों के पास विशेषज्ञता की कमी है अतः निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा इसको दूर किया जा सकता है

(ख) इसी के साथ निजी क्षेत्र आर्थिक रूप से प्रभावी व दक्ष तथा मितव्ययी होता है जिसका लाभ प्रशासन को प्राप्त होगा

(ग) प्रशासन में व्याप्त लाल फीताशाही में कमी आने की उम्मीद की जा रही है

(घ) इससे सिविल सेवकों में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सरकारी सिविल सेवक निजी क्षेत्र के लोगों से प्रभावित होंगे

(च) वर्गीज कुरियन, डॉ मनमोहन सिंह इत्यादि को भी पार्श्व भर्ती के द्वारा प्रशासन में शामिल किया गया था, जिन्होंने अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर विकास में सकारात्मक योगदान दिया

परन्तु इसी के साथ-साथ इस संबन्ध में निम्न लिखित चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं -

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(क) इसका परम्परागत सिविल सेवकों द्वारा विरोध किया जा रहा है जो प्रशासन में नकारात्मकता का समावेश कर सकता है

(ख) इसमे सरकारी लोक सेवक हतोत्साहित हो सकते है

(ग) इसमे भाई-भतीजावाद में वृद्धि हो सकती है क्योंकि इसमे प्रवेश परीक्षा का प्रावधान नही है

(घ) इसमें 'UPSC' की कार्यप्रणाली को महत्व ना देने से संविधान की भावना का उल्लंघन होने की संभावना है।

अतः स्पष्ट है कि पार्श्व भर्ती से प्रशासन में अनेक सकारात्मकताओं का समावेश तो होगा परन्तु इसके संबन्ध में अनेक चुनौतियां भी विद्यमान हैं जिनका उचित विचार-विमर्श के बाद निराकरण किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Identifying the broad contours of the 'Transformation of Aspirational Districts' programme, explain how it adopts a novel strategy to address backwardness. (250 words) 15

नीति आयोग ने हाल ही में आकांक्षी जिलों के संबन्ध में हेल्थ रैंकिंग जारी की है। नीति आयोग द्वारा देश के अतिपिछड़े जिलों के समुचित विकास व उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आकांक्षी जिलों का रूपांतरण कार्यक्रम 2017 में प्रारंभ किया गया है।

यद्यपि देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पहले भी अनेक कार्यक्रमों जैसे पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, द्वीपीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मनरेगा इत्यादि को प्रारंभ किया गया परन्तु अनेक नीतिगत व क्रियान्वयन संबन्धी कमियों के कारण इनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका।

अतः नीति आयोग ने एक नवीन रणनीति अपनाकर इस कार्यक्रम का

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम की नवीन रणनीतियाँ निम्न हैं–

(क) इसमें क्रियान्वयन का स्तर पंचायत संस्थाओं को रखा गया है

(ख) संसाधनों व धन का समुचित व समय पर आवंटन किया जाएगा

(ग) इसमें इन जिलों में कार्यक्रम की प्रगति के मापन हेतु रैंकिंग का प्रावधान है ताकि ये जिले आपस में प्रतिस्पर्द्धा कर सके

(घ) इसमें सभी जिलों के लिए एक समान रणनीति का प्रावधान नहीं है बल्कि सभी जिलों के लिए अलग-अलग क्षेत्रीय रणनीति का प्रावधान है

(च) ~~बिम~~ कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिला स्तर व राज्य स्तर पर समुचित निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार इस कार्यक्रम में पूर्व के कार्यक्रमों में व्याप्त अनेक कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है परन्तु इसकी सफलता के लिए पर्याप्त जनभागीदारी, नागरिक समाज का पर्याप्त समर्थन तथा सम्यक प्रशासनिक व राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. How did India fare on the Millennium Development Goals related to health? In this regard, identify the relevant Sustainable Development Goals and evaluate India's capacity to meet them. **(250 words) 15**

सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2000 से 2015 तक के लिए अपनाया गया था जिसमें वैश्विक विकास से संबन्धित 14 लक्ष्यों का प्रावधान था, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन इत्यादि संबन्धित थे।

भारत ने इन लक्ष्यों के अन्तर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्न प्रकार से प्रदर्शन किया -

(क) भारत में बाल मृत्युदर में गिरावट हुई है जो 'NFHS' के आंकड़ों के अनुसार 41 हो गई है।

(ख) अनेक रोगों जैसे पोलियों, टीबी इत्यादि के प्रसार में कमी

(ग) सकल प्रजनन दर में कमी (2.1)

(घ) टीकाकरण के विस्तार में वृद्धि तथा संस्थागत प्रसवों में वृद्धि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(च) मातृ मृत्यु दर में कमी तथा लिंगानुपात में वृद्धि

हालांकि भारत अभी भी कुपोषण, भुखमरी, स्वच्छता व पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्रों की उपलब्धता के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया है।

संधारणीय विकास लक्ष्यों को 2015-2030 की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है जिनमें स्वास्थ्य से संबन्धित निम्न लक्ष्य शामिल हैं -

(क) स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि

(ख) टीबी का 2030 तक उन्मूलन

(ग) मातृ मृत्यु दर को 2030 तक 100 तथा बाल मृत्यु दर को 25 करने का लक्ष्य

(घ) कुपोषण व भुखमरी के स्तर में कमी

(च) लिंगानुपात में सकारात्मक वृद्धि

(छ) टीकाकरण में प्रसार

सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए जा रहे हैं-

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

(ख) 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम

(ग) जननी सुरक्षा कार्यक्रम

(घ) इन्द्रधनुष कार्यक्रम

@ उपस्थित चुनौतियाँ

(i) बजटीय समर्थन का उचित स्तर पर ना होना

(ii) पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था जिसमें अस्पताल इत्यादि की कमी

(iii) प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी

इस प्रकार अनेक चुनौतियां भारत की 'SDG' लक्ष्यों को पुरा करने की क्षमता में अड़चन डालती है जिनका शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए।

18. What are the different rights recognized under the Forest Rights Act, 2006? Highlight the gaps in the implementation of community forest rights and community forest resource rights granted under the Forest Rights Act. Also, suggest measures to address the current scenario. **(250 words) 15**

जनजातियों के वन अधिकारों को पर्याप्त मान्यता देने तथा उनकी आजीविका एवं आवास की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 पारित किया गया।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित वन अधिकारों को मान्यता दी गई है-

(क) वनों से लघु उपज एकत्रित करने व उनको बेचने के अधिकार

(ख) वनों में जनजातियों के समुदाय द्वारा मत्स्य पालन, खेती इत्यादि को मान्यता

(ग) जनजातियों के वनों से अवैधानिक विस्थापन पर रोक

(घ) ग्रामसभा को इस संबन्ध में अनेक अधिकार प्रदान करना

(ङ) जनजातीय समुदायों को उनकी भूमि का पट्टा प्रदान करना (2005 के पहले

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बसे लोगों को)

(च) जनजातियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों को मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान करना

परन्तु अनेक कारणों के फलस्वरूप जनजातियों को उनके अधिकारों की अपेक्षित प्राप्ति नहीं हुई है जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है -

(क) जनजातियों का अनेक विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन जारी है तथा उनका उचित पुनर्वास नहीं किया जा रहा

(ख) जनजातियों के वन उत्पादों को बेचने की समुचित सुविधा नहीं है

(ग) अनेक राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों इत्यादि के निर्माण के कारण उनके आवास व रोजगार संबन्धी अधिकारों का उल्लंघन

(घ) जनजातियों की परंपराओं के संरक्षण हेतु उचित प्रयासों का अभाव

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस परिदृश्यों को संबोधित करने के उपाय -

(क) जनजातियों के अवैधानिक व जबरन विस्थापन पर रोक

(ख) विस्थापित लोगों को उचित मुआवजा व पुनर्वास की सुविधा

(ग) जनजातीय वन उत्पादों के विक्रय हेतु ट्राइफेड, 'e-NAM' जैसी सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग

(घ) जनजातियों की परंपराओं एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा करने का प्रयास करना

जनजातियों में अभी भी गरीबी, भुखमरी एवं बेरोजगारी की व्यापक समस्या है तथा लाखों लोग विस्थापितों का जीवन जी रहे है जो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है जिसका तत्काल निराकरण आवश्यक है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Progress in India-US ties has been accompanied by equally significant divergences on important issues. Examine in the context of recent developments. (250 words) 15

भारत और अमेरिका के संबन्ध स्वतंत्रता के पश्चात से ही उतार-चढ़ाव भरे रहे है।

हाल ही में घटित अनेक घटनाक्रमों ने अमेरिका व भारत को काफी पास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसमें प्रमुख है-

(क) चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 'क्वाड' का गठन किया है।

(ख) अफगानिस्तान के विकास में भारत व अमेरिका एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

(ग) दक्षिणी चीन सागर व हिन्द महासागर में शांति एवं स्थायित्व का दोनों देश समर्थन करते है। इस संबन्ध में अनेक सैन्य अभ्यास भी किए गए हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(घ) इसी के साथ पाकिस्तान तथा आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों ने 'G20', संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ASEAN इत्यादि मंचों पर समान विचार व्यक्त किए हैं।

(च) इसी के साथ दोनों देश रक्षा व अंतरिक्ष क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी बना रहे हैं। तथा

परन्तु इसी के साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर भारत एवं अमेरिका के मध्य असहमति है जिससे संबन्धों में कटुता का समावेशन हुआ है। इनमें प्रमुख मुद्दे निम्न हैं-

(क) ईरान परमाणु समझौते में अमेरिका के पीछे हटने का भारत द्वारा विरोध किया गया है

(ख) येरुशलम को इजरायल की राजधानी घोषित करने पर भारत का संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ मत देना,

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ग) अमेरिका द्वारा अनेक भारतीय सामानों पर उच्च प्रशुल्कों को आरोपित करने पर भारत का विरोध तथा प्रतिक्रिया

(घ) अमेरिका की H1B वीजा नीति से भारत पर प्रतिकूल प्रभाव

(च) पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने पर भारत द्वारा अमेरिका का विरोध

इसी के साथ हाल ही में अमेरिका ने भारत को ईरान से तेल खरीदने से मना किया है। अतः कहा जा सकता है भारत-अमेरिका के समक्ष अनेक मुद्दों पर सहमति व असहमति विद्यमान है जिनका समाधान आवश्यक है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Despite bonhomie, the structural differences between Indian and Israeli national security situations, their worldviews and absence of explicitly shared enemies limit stronger strategic rapprochement. Critically discuss. **(250 words) 15**

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री इजरायल यात्रा तथा इजरायली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ने दोनों देशों के संबन्धों को काफी मजबूती प्रदान की है। भारत व इजरायल के मध्य सन 1992 में राजनयिक संबन्धों की स्थापना हुई थी इसके पश्चात निरन्तर संबन्धों में सुधार आया है।

भारत व इजरायल के मध्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण संबन्ध है-

(क) कृषि विकास एवं जल संरक्षण का क्षेत्र

(ख) रक्षा उत्पादों की खरीद व विकास जिसमें बराक मिसाइल व 'AWAKS' प्रमुख है

(ग) अन्तरिक्ष क्षेत्र में सहयोग

(घ) आतंकवाद के क्षेत्र में सहयोग

परन्तु भारत व इजरायल के संबन्धों के समक्ष निम्न चुनौतियां विद्यमान है-

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(क) दोनों देश आतंकवाद की समस्या से पीड़ित है परन्तु आतंकवादियों के प्रतिरूप में भिन्नता है

(ख) इजरायल ईरान का धुर विरोधी है जबकि भारत व ईरान के मध्य काफी गहरे संबन्ध है जिससे संबन्धों व हितों में टकराहट होती है।

(ग) चीन के मुद्दे पर भी भारत व इजरायल के अलग-अलग मत है

(घ) इस्लामिक आतंकवाद एवं फिलीस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने के संबन्ध में दोनों देशों के मध्य मतभेद है

(च) दोनों देश भौगोलिक रूप से दूर है तथा दोनों के मध्य कोई साझा शत्रु नहीं है क्योंकि जिस देश का भारत विरोध करता है उसका इजरायल समर्थन जैसे चीन

(छ) इसी के साथ ईरान परमाणु समझौते पर भी दोनों देशों की राय अलग-अलग है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परन्तु इसके बावजूद भी दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित संभावनाएं भी मौजूद है-

(क) भारत इजरायल के नवाचारों का लाभ ले सकता है तथा इजरायली रक्षा उत्पादों को भारत जैसा बाजार मिल सकता है

(ख) कृषि, जल संरक्षण, स्टार्ट अप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक संबन्धों की संभावना

(ग) इजरायल द्वारा आतंकवादी हमलों के खिलाफ विशेषज्ञता का विकास किया गया है जिसका प्रयोग भारत सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने में कर सकता है।

अतः स्पष्ट है कि भारत व इजरायल के संबन्धों में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान है परन्तु साथ ही साथ अनेक व्यापक संभावनाएं भी मौजूद है।